

प्रेषक

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 25 जून, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-2010 में लोक निर्माण विभाग हेतु लेखानुदान में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-10047/32 बजट (सा०)/09-10 दि० 31.3.2009 के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-205(1)/xxvii(1)/09 दिनांक 25.3.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि को संलग्न विवरणानुसार ₹० 905.00 लाख (₹० नौ करोड़ पाँच लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अब अवमुक्त की जा रही धनराशि में केवल चालू कार्य एवं अनुरक्षण आदि के कार्य ही सम्पादित किये जायेंगे।

3- वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी०एम०-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह की व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (मा० मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4- प्लान पक्ष की उक्त योजनाओं की सी०सी०एल० प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष पर दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करावे ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण, यदि पुनः सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का भी यह दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिरात के अनुसार सी०सी०एल० निर्गत करेंगे।

1000

- 5- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग- I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।
 - 6- उत्तराखण्ड में लागू समस्त प्रोक्पोरमेंट क्लस के अधीन ही समस्त प्रक्रियाएँ पूर्ण की जायेगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
 - 7- साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस संबंध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 - 8- 15 नवंबर एवं 15 जनवरी को प्रत्येक दशा में excess saving statement निर्धारित प्रपत्र पर प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 9- न्यायालय की आज्ञाधियों के भुगतान मद में भुगतान करने से पूर्व शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
 - 10- साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाये एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रसार-17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 11- जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुरक्षित विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 12- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की अनुदान संख्या 22 के क्रमशः सलग्नक 1, 2, 3 व 4 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा जायेगा।
 - 13- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यूओ.-126 /XXVII(2)/2009 दिनांक 17 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोपदि।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या-1855 (1)/111(2)/09-03(बजट)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओवरसै मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

शासनादेश सं० 1855 / 111(2) / 09-03(बजट) / 09 दिनांक 25 जून 2009 का संलग्नक-1

लोक निर्माण विभाग

अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-3054 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत)

(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	मद/योजना का नाम /उपमद	अवमुक्त धनराशि
1	2	3
1.	प्रदेश के मार्ग एवं पुलिया का अनुरक्षण 3054- सड़क तथा सेतु 04- जिला तथा अन्य सड़कें 337- अनुरक्षण एवं मरम्मत 03- अनुरक्षण एवं मरम्मत 0301-प्रदेश के मार्ग एवं पुलिया का अनुरक्षण 24- वृहत निर्माण कार्य	750.00
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के अधिकार रक्षित धनराशि 3054- सड़क तथा सेतु 80-सामान्य-800 अन्य व्यय 03- निर्माण 0301-मुख्य अभियन्ता स्तर-1के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यो आवश्यक रक्षित धनराशि 24- वृहत निर्माण कार्य	5.00
	योग:-	755.00

(रु० सात करोड़ पचपन लाख मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

Khas

शासनादेश सं०-1855/111(2)/09-03(बजट)/09 दिनांक 25 जून, 2009 का संलग्नक -2

लोक निर्माण विभाग

अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 (आयोजनागत)

(धनराशि लाख रु० में)

क्र. सं.	मद/योजना का नाम /उपमद	अवमुक्त धनराशि
1	2	3
1.	बाढ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण 5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला तथा अन्य सड़कें 800- अन्य व्यय 03- राज्य सेक्टर 06- बाढ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण 24- बृहत निर्माण कार्य	100.00
2.	क्रानिक रिसप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था 5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला तथा अन्य सड़कें 800- अन्य व्यय 03- राज्य सेक्टर 07- क्रानिक रिसप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था 24-बृहत निर्माण कार्य	50.00
	योग :-	150.00

(रु० एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
अपर सचिव।